

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक :/7 मई, 2016

विषय : स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या K-15017/01/2015-SC-1, दिनांक 01.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्य राज्यों के नगरों के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चिन्हित देहरादून नगर हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने के सम्बन्ध में ₹ 200.00 लाख स्वीकृत कर अवमुक्त किये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 200.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 66.67 लाख व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि कुल ₹ 66.67 लाख (₹ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रस्ताव/डी0पी0आर0 तैयार कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- कार्यों की स्वीकृति के समय कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू-बिड सिस्टम पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि सक्षम व अनुभवी फर्मों/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाए तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।

कमश:..../2

(2)

- (vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/ 2006 दिनांक 30.05.2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
- (vii) स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।
- (viii) कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र यथासमय शासन को प्रस्तुत किए जायेंगे। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- (ix) धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान के अनुदान संख्या 13 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-12-स्मार्ट सिटी योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 71/XXVII(2)/2016, दि0 13 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-एलॉटमेन्ट आई0डी0S./60513022/

भवदीय,

(डी0एस0 गबर्वाल)
सचिव।

संख्या-776/IV(2)-शा0वि0-16-74(सा0)/14, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।